



2026:AHC-LKO:20620

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ**आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या-1587 वर्ष 2026**

शिव बालक यादव

..... आवेदक(ओं)

बनाम

भारत संघ, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, लखनऊ के माध्यम से

.....विपक्षी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : कौशल किशोर तिवारी, शक्ति

विपक्षी(ओं) के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार अवस्थी

न्यायालय संख्या – 15**माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अखिलेश कुमार अवस्थी विद्वान अधिवक्ता को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से सुना।

वर्तमान आवेदन अपराध संख्या 19/2025 धारा 8/20/29 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, पुलिस स्टेशन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, महानगर, जिला लखनऊ में जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि जब पुलिस पार्टी गश्त ड्यूटी पर थी, तो उन्हें एक मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि चार व्यक्ति, अवैध तस्करी के साथ, बस संख्या यूपी 78 केटी 5257 में यात्रा कर रहे थे और बरेली की ओर जा रहे थे। उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो अधिकारियों ने सिधौली पुलिस स्टेशन के पास उक्त बस को रोक लिया। आरोप है कि प्रत्येक आरोपी व्यक्ति द्वारा अलग-अलग ले जाए गए बैग से कुल 31 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि कथित तलाशी और जब्ती एक सार्वजनिक बस में हुई थी जिसमें कई यात्री मौजूद थे; हालाँकि, केवल कंडक्टर का बयान दर्ज किया गया है और किसी स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पूरे फर्द बरामदगी में यह भी नहीं बताया गया है कि किस विशेष बैग से कथित प्रतिबंधित सामग्री के कितने पैकेट बरामद किए गए थे। फर्द बरामदगी में लापरवाही से दर्ज किया गया है कि छापेमारी टीम और तथाकथित स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में, सभी चार आरोपियों ने कबूल किया कि बैग में गांजा था। आगे आरोप है कि उक्त बैगों से कुल 17 पैकेट बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 31 किलोग्राम था, लेकिन प्रत्येक आरोपी के संबंध में कोई विशिष्ट आरोप या पृथक्करण नहीं किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि कथित तलाशी और जब्ती स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। यह तर्क दिया गया है कि किसी सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व वारंट या प्राधिकरण प्राप्त किए बिना सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तलाशी ली गई थी, और यह प्रदर्शित करने के लिए पत्रावली पर कोई सामग्री नहीं है कि विश्वास के आधार को दर्ज करने और उसे वरिष्ठ अधिकारी को अग्रेषित करने की अनिवार्य आवश्यकताओं, जैसा कि धारा 42 (1) के प्रावधान के तहत माना गया है, का अनुपालन किया गया है। इस तरह का गैर-अनुपालन पूरी तलाशी और जब्ती को खराब कर देता है।

आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कथित बरामदगी चार आरोपी व्यक्तियों के संयुक्त कब्जे से दिखाई गई है। हालाँकि, वर्तमान आवेदक को कोई विशेष भूमिका नहीं दी गई है। कथित तौर पर आवेदक के बैग से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ है, और अभियोजन पक्ष अपनी ओर से सचेत कब्जा स्थापित करने में विफल रहा है।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक को सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किसी भी कथित मादक पदार्थ ले जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52 क का अनुपालन नहीं किया गया है, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती, नमूनाकरण और प्रमाणीकरण के लिए उचित प्रक्रिया को अनिवार्य करता है।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक ने जमानत आवेदन के प्रस्तर 29 में एक मामले का आपराधिक इतिहास बताया है और वह 13.10.2025 से जेल में है।

आगे कहा गया है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक के भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत मिल गई है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता, श्री अखिलेश अवस्थी ने जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों की मंशा समान थी और वे सचेत रूप से प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे में थे।

पत्रावली का अवलोकन किया।

फर्द बरामदगी को देखने से पता चलता है कि इसे बहुत ही सामान्य तरीके से तैयार किया गया है। जांच एजेंसी आसानी से बता सकती थी कि प्रत्येक आरोपी के पास से कितने पैकेट गांजा बरामद हुआ और किस बैग से। हालाँकि, इस महत्वपूर्ण विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे वसूली पर संदेह पैदा होता है।

आवेदक का यह तर्क कि उसके बैग से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, इस स्तर पर सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 29 के अर्थ के तहत आरोपी व्यक्तियों के बीच उकसावे या आपराधिक साजिश का अनुमान लगाने के लिए वर्तमान में पत्रावली पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। हालाँकि आवेदक को सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ पकड़ा गया था और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उनमें से प्रत्येक पर बैग ले जाने का आरोप है, फर्द बरामदगी में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि प्रत्येक आरोपी के बैग से कितना प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था।

अभियोजन पक्ष का दावा है कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से काम कर रहे थे और उनके पास सचेत रूप से प्रतिबंधित पदार्थ था, जो मुकदमे के दौरान अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। इस स्तर पर, आवेदक संदेह का लाभ पाने का हकदार है, विशेष रूप से वसूली के विशिष्ट आरोप के अभाव में।

उपरोक्त और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक ने जमानत आवेदन के प्रस्तर 29 में एक मामले के अपने आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है, जिसमें गांजा की व्यावसायिक मात्रा से कम की वसूली शामिल है; आवेदक दिनांक 13.10.2025 से न्यायिक हिरासत में है; इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले से, यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान आवेदक के बैग से कथित तौर पर बरामद मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आती है या नहीं, न ही उसके लिए जिम्मेदार सटीक मात्रा का खुलासा किया गया है, इस प्रकार, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 (1) (ख) के तहत विचार की गई जुड़वां शर्तें संतुष्ट प्रतीत होती हैं, क्योंकि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक कथित अपराध का दोषी नहीं हो सकता है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *अमरसिंह रामजीभाई बारोट बनाम गुजरात* राज्य में निर्धारित कानून के मद्देनजर, (2005) 7 एससीसी 550 में रिपोर्ट की गई और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे आवेदक को जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता है। तदनुसार, जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त मामले में अपराध संख्या में शामिल आवेदक **शिव बालक यादव** को न्याय के हित में लगाए गए निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधन और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए: -

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/धमकी नहीं देगा।
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iv) आवेदक को इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करना होगा कि जब गवाह अदालत में मौजूद हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तारीखों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त में चूक होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानेगा और कानून के अनुसार आदेश पारित करेगा।
- (v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। बिना पर्याप्त कारण के उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत कार्यवाही कर सकता है।
- (vi) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा करता है। जारी किया जाता है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत, कानून के अनुसार, उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

मार्च 20, 2026

मधु जे.आर./पी.एस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।